ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No. :UPBIL04292,
RNI REG. No.: UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No.: 561/2013-14 Vol.-5, No.-II, PP-184-186, YEAR- DEC.2016

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उच्चशिक्षा की अवधारणा

❑ डॉ0 श्रीमती गीता शुक्ला

वर्तमान सहस्त्राब्दि की अनेक विशेषताओं में शामिल वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे बचना किसी भी राष्ट्र के लिए कठिन है। वस्तुतः वर्तमान समय का वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भारतीय "वसुधैवकुटुम्बकम" की एकात्मवादी धारणा पर आधारित नहीं है वरन् अमेरिका व यूरोप से चल कर आयी एक ऐसी अवधारणा जिसका आधार सूचना प्रौद्योगिकी है। ई–गति पर आधारित त्वरित संचार व्यवस्था नेविश्व को औद्योगिक समाज के स्थान पर सूचना आधारित समाज का स्वरूप देकर राष्ट्रों के बीच की दीवारें तोड़कर 'वैश्विकगांव' की संकल्पना को साकार कर दिया है। फलस्वरूप सामाजिक अंतः क्रिया में समय व स्थान की सीमाएं समाप्त हो गयी है।

किसी देश का सम्पूर्ण विश्व की विचारधारा की दिशा में ढलना ही वैश्वीकरण है। विकसित शब्दों की दृष्टि से वैश्वीकरण की परिभाषा इस प्रकार है–'वैश्वीकरण से तात्पर्य उन सीमाओं को समाप्त करने से है जो देश के आर्थिक विकास में बाधक है।' इसके द्वारा प्रत्येक देश दूसरे देशों तक अपनी राज्य पहुँच बना सकेगा जिसके द्वारा निर्धन राष्ट्र धनी राष्ट्रों के बाजार तक पहुँच सकेंगे। अतः वैश्वीकरण का अर्थ पूरे देश को एक वैश्विक वित्तीय गांव बनाना है। ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी (1665)के अनुसार, 'भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीति एवं व्यापारिक क्षेत्रों से लेकर संगीत, वेशभूषा एवं जनमीडिया के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत द्रुतगामी से प्रभावित हुआ है। 'अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, यूनेस्को के निदेशक डॉ. गुडमंड हर्नेस ने वैश्वीकरण को मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार सामान्य रूप से भूमण्डलीकरण मानव समाज और संस्कृति के विस्तार की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। प्रो0जे0जे0ब्रनर के अनुसार, सामान्य तौर परअन्तर्निर्भिता, किसी ने निरुद्देश्य और दिक–काल संकुचन, तो किसी ने नक्षत्र विश्रांत के वास्तविक समय इकाई के अनुसार पर्यावरण परिवर्तन की प्रक्रिया कहा है। राजनीतिक संदर्भों में यह अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी सीमांकन के बीच की दीवार को कमजोर करने की प्रक्रिया नजर आता है। इससे संप्रभुता का एक नया रूप और राष्ट्र–राज्य की नई अवधारणा विकसित होती है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भूमण्डलीकरण राज्य और बाजार के बीच के संबंध का रूपांतरण, विश्व–व्यापार का प्रसार और अधिमान्यता, राष्ट्रों के बीच तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, पर्यावरण विनाश और आंतरिक संकट विशेषकर वित्तीय संकट को इंगित करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भूमण्डलीकरण बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज का द्योतक है। यह सामाजिक बहुलता, भूमण्डलीकरण संप्रेषण उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय अस्मिता और प्रतीकों के प्रवाह, सभ्यताओं एवं समुदायों के बीच संघर्षों के परिणाम विभिन्न आस्थानो, मूल्यों और परंपराओं के अंतर्गत निर्मित होगी। उपर्युक्त विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा व संस्कृति महत्वपूर्ण आयाम है। भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद का जन्म हो रहा है। विश्व के सभी राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शैक्षणिक पक्षों के एक ही व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय मौलिक परिवर्तनों के दौर का है। प्रो0जे0जे0ब्रनर के अनुसार, मौलिक परिवर्तनों के माध्यम से ही शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार विद्यालय की अवधारणा अस्तित्व मेंआयी,उसके बाद सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ और अभी

❑ एसो. प्रो. बी. एड्. एम. डी. पी. जी. कॉलेज प्रतापगढ़ (उ0प्र0), भारत

हाल में जन शिक्षा का एक अभियान बनी हुई है। मेरी परिकल्पना है कि शिक्षा में चौथी क्रांति समान प्रभाव से आ रही है। यह शैक्षिक क्रांति वैश्वीकरण का परिणाम है। आज हम वैश्वीकरण के परिवेश में हैं। उसमें विद्यालय के संदर्भ और उद्देश्यों में शैक्षिक सामग्री और बौद्धिक दबाव के साथ तीव्र गति से रूपांतरण हो रहा है। आज विश्व स्तर पर सूचना समाज के निर्माण की दिशा के सम्मुख अप्रत्याशित परिवर्तन और समायोजन की चुनौती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यापकता, तीव्रता, गति, दिशा और प्रवाह और परस्पर अनुक्रिया नेसभी देशों कोशिक्षा और राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, सूचना और दूरसंचार संप्रेषण तकनीक के आध ार पर प्रौद्योगिकी की स्थापना जो शिक्षा के लिए नया परिवेश निर्मित कर रही है, के बीच सहसंबंध की पुनः समीक्षा करने को विवश किया है।

सूचना तकनीकी में हो रहे विकास ने ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिक्षा लोगों के घरों तक पहुँच चुकी है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों मेंहो रहे नवीनतम परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए सूचना तकनीक का प्रयोग अपरिहार्य हो गया है। वर्तमान पाठ्यक्रमों में अप्रासांगिक और पुराने हो चुके विवरणों की कटाई–छंटाई अत्यावश्यक है। जिसमें वर्तमान पाठ्यचर्चा को नवीनतम बनाया जा सके।

राष्ट्र के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन हेतु भारत में 1991 से आर्थिक उदारीकरण कीनीति को अपना कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया गया है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अन्य राष्ट्रों सहित भारत ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया हैकी शिक्षा–व्यवस्था विशेषतः उच्च शिक्षा को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार चलना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा का संबंध कभी इतना सशक्त व प्रत्यक्ष नहीं था जितना कि वैश्वीकरण के प्रभाव से दृष्टिगोचर हो रहा है। शिक्षा के संबंध में वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण घटक एक ऐसी मानव शक्ति का सृजन भी है जो विश्वबाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सके। इसका सीधा अर्थ यह है कि सबसे अधिक क्षमता वाले व्यक्तियों को ही उच्चशिक्षा उपलब्ध करायी जाये। वैश्वीकरण की जरूरत के मुताबिक शिक्षा के विकास हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी। जबकि भारत सहित विकासशील देश संसाधनों की कमी की समस्या से पहले से ही जूझ रहे हैं। भारत सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% खर्च करती है जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। जर्मनी शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, ब्रिटेन 5.4%, फ्रांस 6.1% और स्वीडन 8.1% खर्च करता है। भारत सरकार ने भीशिक्षा परसकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का वायदा किया था जिसे पूर्ण करने में असफल रही है। इसीलिए लगातार उच्च शिक्षा को प्राथमिकता की सूची से बाहर रखने के सुझाव दिए जा रहे हैं। उद्योग और व्यापार जगत की बेहतरी के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों मुकेश अंबानी तथा कुमार मंगलम बिड़ला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुफ्त प्रदान करनी चाहिए किन्तु उसके बाद सरकार को उसमें पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकिउच्च शिक्षा का लाभ व्यक्ति स्वयं उठाता है अतः उसके लिए उसे खुद भुगतान करना चाहिए। यद्यपि उच्च शिक्षा में कटौती का यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है क्योंकि उच्च शिक्षा का वित्तपोषण कम करने पर उसका विस्तार और गुणवत्ता प्रभावित होगी जिससे योग्य अध्यापकों की आपूर्ति भी बाधक होगी।वस्तुतः शिक्षा एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके विभिन्न क्षेत्र और चरण एक दूसरे के पूरक हैं। इसका वर्गीकरण करके किसी क्षेत्र या चरण के वित्तपोषण में कटौती करना शिक्षा की प्रगति और दूरगामी विकास को अवरुद्ध करना होगा।

भारत में उच्च शिक्षा के स्तर के दो किनारे दिखलाई पड़ते हैं एक ओर तो आई0आई0एम0 और आइ0आइ0टी0 जैसी विश्वस्तरीय संस्थाएँ हैं जहाँ पर शिक्षा गुणवत्ता के पैमाने पर कहीं से भी कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर अभिन्न ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है जहाँ न तो अधोसंरचना के नाम पर कुछ है, न स्तरीय पुस्तकालय है, नसुयोग्य अध्यापक हैं, यदि है, तो भी विद्यार्थियों की संख्या और उनकी संख्या में अनुपात का कोई मानक नहीं है। भारत के अधिकांश शिक्षण संस्थानों की यही स्थिति है। एक ओर

जहाँ देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की संख्या सीमित है और प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है, वहीं पर अधिकांश संस्थाएँ ऐसी है जहाँ न तो प्रवेश संख्या निश्चित है और न ही उनके लिए किसी प्रकार का मापदण्ड है। अध्यापकों की गुणवत्ता को तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति भी कम प्रभावित नहीं कर रही है। बहुसंख्यक संस्थानों में फीस बटोरने के नाम पर सबको घर से बुला–बुलाकर प्रवेश दिया जा रहा है जिससे प्रबंधतंत्र को लाभ मिल सके। यह न सिर्फ निजी क्षेत्र बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी हो रहा है। विद्यार्थियों की संख्या अधोसंरचना व शिक्षकों के अनुपात में कहीं अधिक होने से गुणवत्ता का प्रभावित होना नितांत अपरिहार्यहै। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना होगा। ना सिर्फ छात्रों की उपस्थिति अपितु अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

वस्तुतः तो सच्चाई तो यह है कि वैश्वीकरण से उचित समायोजन स्थापित करने के लिए गुणात्मक उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है।

वर्तमान वैश्विक समुदाय के युग में यदि भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आना है तो जापान की भाँति अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार सीमित व नियंत्रित वैश्वीकरण को अपनाकरउच्च शिक्षा का स्वदेशी मॉडल तैयार करना होगा। वैश्वीकरण के इस दौर में यदि प्रत्येक अवसर का सर्वाधिक लाभ नहीं उठाया गया तो हम पीछे छूट जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर संसाधन आवंटन की नीति में बदलाव हो और राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाए। उपर्युक्त सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के जरिए हमें एक उच्च बौद्धिकताकेनए भारत कोविश्व के सामने लानेसे कोई नहीरोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के ये शब्द सार्थक हो सकेंगे–'सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है नही यहकोरी कल्पना है बल्कि यह ऐसा ध्येय है जिसे हम सब को अपनाना चाहिए।' हम इससे अवश्य सफल होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जे0एलन जॉनसन, द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, 1995.
2. जे0जे0 ब्रनर, भूमण्डलीकरण शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्रांति,परिप्रेक्ष्यअंक जीरो 09 अप्रैल 2003.
3. वही।
4. जे0एल0 आजाद, भूमण्डलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव, पूर्व सलाहकार शिक्षा प्रभाग योजना, भारत सरकार।
5. देवर्षि शर्मा, उद्देश्यविहीन उच्चशिक्षा, दैनिक जागरण 22 जनवरी 2001.
6. राज अग्रवाल, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, प्रेस नई दिल्ली 2002.
7. डी0के0 पालीवाल, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, प्रेस नई दिल्ली 2002.